



राजनांदगांव जिले में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन (महिला आर्थिक सशक्तिकरण के विशेष परिपेक्ष्य में)

डॉ. के पद्मावती¹, मंजु²

¹ सहायक प्रधायपक अर्थशास्त्र, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशाष्टि महाविद्यालय, दुर्ग (छ. ग.)

² शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशाष्टि महाविद्यालय, दुर्ग (छ. ग.)

ABSTRACT

केन्द्र सरकार ने पाँच करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी दर में वृद्धि की घोषणा की गयी है जिससे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। स्थानीय जिला आयुक्तों को काम आवंटित करने और तदनुसार निधि का उपयोग करने के लिए अधिकार दिया गया है जो ग्रामीण महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए उनके क्षेत्र में आपेक्षित आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

यह योजना भारत में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित है। प्रत्येक राज्य में जिले हैं, फिर जिलों के भीतर ब्लॉक और ब्लॉकों के भीतर वार्ड हैं इस योजना के तहत ब्लॉक में सार्वजनिक कार्य से संबंधित रोजगार दिया जाता है। एवं धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी की जाती है। राज्य फिर स्थानीय निकायों द्वारा राज्यों को धन देते हैं जिससे सभी मजदूरों के खाते ग्राम पंचायतों से पंजीकृत होते हैं।

KEYWORDS: मनरेगा योजना, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, आधिनियम,

प्रस्तावना

राजनांदगांव 26 जनवरी सन् 1973 को तात्कालिक दुर्ग जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया रियासत काल में राजनांदगांव एक राज्य के रूप में विकसित था। एवं यहाँ पर सोमवशी कलचुरी एवं मराठाओं का शासन रहा। पूर्व में यह नंदग्राम के नाम से जाना जाता था। यहाँ की रियासत कालीन महल, हवेली, राजा मंदिर इत्यादि स्थान इस जगह की गौरवशाली समाज संस्कृति परम्परा एवं राजाओं की कहानी कहता है। साहित्य के क्षेत्र में श्री गजानंद माधव मुकितबोध एवं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरखी तथा बलदेव प्रसाद मिश्र का योगदान विशिष्ट रहा है। 1 जुलाई सन् 1998 में इस जिले के कुछ हिस्से को अलग कर एक नया जिला कबीरधाम की स्थापना हुई जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में स्थित है। जिला मुख्यालय राजनांदगांव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मार्ग में स्थित है। राष्ट्रिय राजमार्ग 6 राजनांदगांव से होकर गुजरता है।

मनरेगा योजना को भारत सरकार द्वारा एक रोजगार गारंटी के रूप में लागू किया गया है इस योजना को विधान सभा द्वारा 7 सितम्बर 2005 को पारित किया गया उसके बाद 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू कर दिया गया। मनरेगा योजना को शुरुआत में राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया मनरेगा योजना विश्व की एक मात्र ऐसी योजना है जो ग्रामीण मजदूरों को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी देती है। देश की ग्रामीण गरीब और बेरोजगार परिवार को अजीविका के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है जिससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण की अवधारणा: महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, महिलाओं को आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से उसे सशक्त (मजबूत) बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। कुछ समय पूर्व विश्व आर्थिक मंच की तरफ ग्लोबल जैंडर इंडेक्स नामक एक आयोजन किया गया था जिसमें सभी राष्ट्रों की लैंगिक समानता को दर्शाया गया और वहां भारत का स्थान 87 वां था जिसमें ये साबित हो जाता है कि अभी हम कितने पिछे हैं और हमारे देश का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं इन्हीं सब अवधारणा को देखते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। तथा महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जायेगा।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता :

सशक्तिकरण से तात्पर्य कि किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें योग्यताएँ आ जाती हैं जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो।

लैंगिक असमानता भारत में मुख्य समाजिक मुद्दा है जिसमें महिलाएँ पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ती जा रही हैं। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती हैं। और ये महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर महत्व मिले। परंतु वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए न केवल घरेलू और परिवारिक जिम्मेदारियों बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए और अपने आस पास एवं देश में होने वाली घटनाओं को भी जानना चाहिए।

महिलाओं को सशक्त बनाने में मनरेगा की भूमिका :

महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) महिलाओं को कार्य देने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बना रहा है। मनरेगा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तेज काम दिया जा रहा है। और इस योजना में श्रमिक के रूप में महिलाएँ शुरू से ही काम कर रही हैं लेकिन अब इसमें 50 फीसदी महिलाओं को जो मनरेगा में तीन साल से काम कर रही हैं उन्हें मेट बनने का अवसर दिया गया है। राजनांदगांव जिले में 4 विकासखण्ड हैं एवं इन सभी विकासखण्डों में मनरेगा कार्य संचालित है – राजनांदगांव में 112 ग्राम पंचायत एवं डोगरांव में 76 ग्राम पंचायत और डोगरांव में 102 तथा छुरिया में 118 ग्राम पंचायत हैं जिसमें हर साल मनरेगा का काम संचालित किया जाता है।

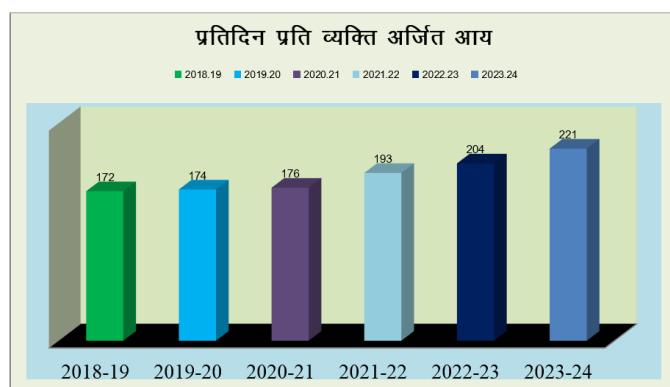
50 मनरेगा मजदूरों पर एक मेट काम करता है। मनरेगा के तहत जहाँ काम हो रहा है वहां पर 50 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो उन पर एक को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

मनरेगा योजना के आर्थिक प्रभाव : महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गांर्टी योजना – इस योजना के तहत (6 जनवरी 2023 तक) कुल 5.6 करोड़ परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ और 225.8 करोड़ दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। मनरेगा के तहत कार्यों और रोजगार के अवसर साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं वित्त वर्ष 2022 में 85 लाख कार्य पूरे किए गये और वित्त वर्ष 2023 में 9 जनवरी 2023 तक 70.6 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं। इन कार्यों में तलाब खोदना, कुएं बनाना, पौधा रोपण आदि के लिए लाभार्थियों को श्रमिक और निर्माण सामग्री उचित दर पर प्राप्त होते हैं इसी तरह से दो से तीन साल की छोटी सी अवधि में इस तरह की उपायों का कृषि उत्पादकता उत्पादन संबंधी खर्च, प्रति, परिवार, आय प्रवास में कमी, गैर संस्थागत स्त्रोतों से बेवजह के ऋण लेने से काफी हद तक सकारात्मक असर पड़ा है। ग्रामीणों के जीवन में बेहतरीन बदलाव के लिए बल दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण गांर्टी योजना मनरेगा के तहत रोजगार के लिए मांग में कमी आई है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है।

वित्तीय वर्ष	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय
2018 - 19	172
2019 - 20	174
2020 - 21	176
2021 - 22	193
2020 - 23	204
2023 - 24	221

तालिका क्रमांक - 1

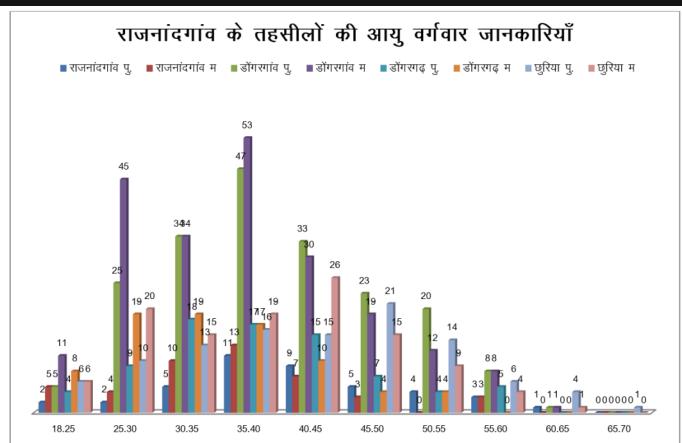
मनरेगा के अन्तर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण वित्तीय वर्ष 2018 – 19 से 2023 – 24 तक



शोध उपलब्धियाँ: उपयुक्त समंको के विश्लेषण से निम्नलिखित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं

राजनांदगांव जिले में मनरेगा कर्मियों की संख्या

आयु वर्ग	राजनांदगांव		डोंगरगांव		डोंगरगढ़		छुरिया		कुल	
	पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म
18-25	2	5	5	11	4	8	6	6	17	30
25-30	2	4	25	45	9	19	10	20	46	88
30-35	5	10	34	34	18	19	13	15	70	78
35-40	11	13	47	53	17	17	16	19	91	102
40-45	9	7	33	30	15	10	15	26	72	73
45-50	5	3	23	19	7	4	21	15	56	41
50-55	4	0	20	12	4	4	14	9	42	25
55-60	3	3	8	8	5	0	6	4	22	15
60-65	1	0	1	1	0	0	4	1	6	2
65-70	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
कुल	42	45	196	213	79	81	106	115	423	454



राजनांदगांव जिले में मनरेगा कर्मियों की संख्या –

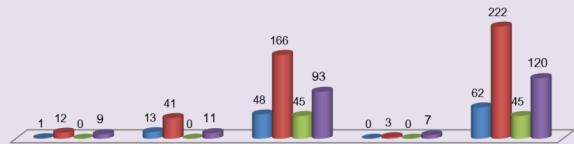
- मनरेगा कर्मियों की संख्या राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव विकासखण्ड में 42 पुरुष एवं 46 महिलाएँ, डोंगरगांव विकासखण्ड 196 पुरुष एवं 213 महिलाएँ हैं तथा डोंगरगढ़ विकासखण्ड में 79 पुरुष एवं 81 महिलाएँ और छुरिया विकासखण्ड में 106 पुरुष तथा 115 महिलाएँ मनरेगा कर्मियों के रूप में अपने सेवाएँ दे रही हैं।
- लैंगिक अनुपात राजनांदगांव जिले में कुल 877 मनरेगा कर्मी हैं जिसमें से पुरुष 423 तथा महिलाएँ 454 हैं। इसमें यह भी सपष्ट होता है कि पुरुषों के तुलना में महिलाएँ अधिक हैं।

राजनांदगांव जिले के विभिन्न वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या:

क्रमांक	विकासखण्ड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	योग
1.	राजनांदगांव	1	13	48	0	62
2.	डोंगरगांव	12	41	166	3	222
3.	डोंगरगढ़	0	0	45	0	45
4.	छुरिया	9	11	93	7	120
	योग	22	65	352	10	449

राजनांदगांव जिले के विभिन्न वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या

■ राजनांदगांव ■ डोंगरगांव ■ डोंगरगढ़ ■ छुरिया



उपयुक्त समंको के विश्लेषण से निम्नांकित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं :-

- राजनांदगांव जिले के विभिन्न वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या, राजनांदगांव जिले में 4 विकासखण्ड हैं – राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, इन सभी विकासखण्डों में कुल 22 अनुसूचित जाति एवं 65 अनुसूचित जनजाति और 352 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 10 अन्य जाति वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या हैं।
- राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव विकासखण्ड में कुल 449 वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या हैं।

सुझाव: ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की कमी एवं उनके विकास में सबसे ज्यादा अवरोधक का कार्य कर रही है अतः महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में लड़कियों की शिक्षा के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के सिद्धांत में कोई कमी नहीं हैं लेकिन इसका जिस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा हैं वह प्रक्रिया दोषपूर्ण हैं। अतः इस योजना के क्रियान्वयन के दोषों को दूर करने पर जोर दिया जाना चाहिये।

मनरेगा योजना को अधिक प्रभावी तथा परिणाममूलक बनाने के लिए आवश्यक हैं कि जवाबदेही के साथ-साथ ग्राम पंचायतों को उसकी स्थानीय जरूरत के अनुसार कार्य चुनने और मनरेगा लाभार्थियों को भागीदारी बनाने के लिए ज्यादा अधिक दिया जाए।

मनरेगा अधिनियम में महिला श्रमिकों विधावा, तलाक शुदा, अविवाहित के लिए मुख्य जीविकोपार्जन हैं। इससे प्राप्त होने वाले मजदूरी दर उनके आर्थिक आर्जन का स्त्रोत हैं मजदूरी दर भुगतान के देशी से उनकी आर्थिक स्थिति में बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मजदूरी दर की भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष उपरोक्त समंको के विश्लेषण से यह पाया गया है कि वर्तमान परिवेश में रोजगार को देश की आर्थिक स्थिति का प्रतिक माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना दिनों दिन बढ़ता जा रहा हैं एवं गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण हैं जैसे-शिक्षा, स्वच्छता, लघु सिचाई, पेयजल सड़कों का निर्माण आदि कार्यों का दायित्व पंचायतों का होता है। इस प्रकार के कार्यों का संचालन से ही ग्रामीण लोगों के पलायन की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया हैं लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे की प्रत्येक पंजीकृत परिवार को लाभ प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची शोध पत्र एवं पुस्तकों:

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग –2007
2. महात्मा गांधीराष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005,
3. मिश्र, डॉ. जगन्नाथ. (1998). भारतीय आर्थिक विकास की नई प्रकृतियाँ. विकास पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली,
4. छत्तीसगढ़ जनसंख्या रिपोर्ट 2011 जिला पंचायत, राजनांदगांव

ग्रंथ सूची:

1. narega.nic.in
2. narega.net
3. mgnrega.cg.gov.in
4. knowledge.nrega.net